



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 09]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 10, 2017/पौष 20, 1938

No. 09]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 10, 2017/PAUSA 20, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2017

Case No. SSR-3/2017

(निर्णायक समीक्षा जाँच)

विषय : चीन जन. गण., से सैकरीन के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरूआत

फा. सं. 15/23/2016 -डीजीएडी: 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी कहा गया है) ने दिनांक 4 जुलाई, 2005 की अधिसूचना सं. 14/27/2004-डीजीएडी द्वारा चीन जन. गण. से सैकरीन के कथित पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की पाटनरोधी जाँच की शुरूआत की। प्रारंभिक जाँच परिणाम 1 अप्रैल 2006 को जारी किए गए और अंतिम जाँच परिणाम 3 जनवरी 2007 को जारी किए गए थे। वित्त मंत्रालय की दिनांक 19 मार्च, 2007 की अधिसूचना द्वारा चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) से सैकरीन (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

2. तत्पश्चात, प्राधिकारी ने 31 मई, 2010 की अधिसूचना द्वारा उक्त पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरूआत की थी और दिनांक 7 दिसंबर, 2011 की अंतिम जाँच परिणाम अधिसूचना सं. 15/20/2010 के माध्यम से उक्त देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की और सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 7/2012-सीमशुल्क दिनांक 13 जनवरी, 2012 द्वारा शुल्कों को आगे 5 वर्ष की अवधि अर्थात् 12 जनवरी, 2017 तक के लिए बढ़ाया गया था

क. निर्णायक समीक्षा की शुरूआत

3. यतः नियमावली के नियम 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1995 की धारा 9क(5) के अनुसार उक्त अधिनियम के अधीन लागू पाटनरोधी शुल्क लागू पाटनरोधी शुल्क को यदि उससे पहले न हटाया जाए और यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा शुल्क की

अवधि समाप्त होने से पहले की गई समीक्षा में यह निष्कर्ष न हो कि शुल्क के समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, तो शुल्क उनके लागू होने की तारीख से पाँच वर्षों के बाद वह निष्प्रभावी हो जाते हैं। उक्त के अनुसार उपाय की अवधि समाप्त होने की तारीख से तर्कसंगत अवधि के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर प्राधिकारी के लिए इस बात की समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क के समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की आशंका है।

4. और यतः मै. स्वाति पेट्रो प्रोडक्ट्स प्रा. लि., मै. श्री वरदायिनी कैमिकल इंड. प्रा. लि. और मै. ए एस कैमोप्लार्मा प्रा. लि. (जिन्हें आगे याचिकाकर्ता कहा गया है) द्वारा अधिनियम और नियम के अनुसार एक याचिका दायर की गई है जिसमें उक्त देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित उक्त वस्तु के पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति का आरोप लगाते हुए शुल्क की अवधि को आगे 5 वर्षों के लिए बढ़ाने के लिए सैकरीन के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत करने की मांग की गई है।

ख. समीक्षा के लिए आधार

5. यह अनुरोध इस आधार पर लागू पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के लिए है कि संबद्ध वस्तु का पाटन संबद्ध देश से भारी मात्रा में जारी है और उपाय की समाप्ति से उस देश से पाटन के जारी रहने और तेज होने की संभावना है क्योंकि संबद्ध देश में आधिक्य क्षमता उपलब्ध है और उस देश के उत्पादकों में अत्यधिक निर्यातानुमुखता है। यह अनुरोध किया गया है कि यद्यपि पाटनरोधी शुल्क के लागू होने के कारण घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार हुआ है तथापि शुल्क के हटने से पाटन के तेज होने और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना है क्योंकि संबद्ध देश से पाटन आयातों के भारी कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री के प्रभाव पड़े हैं।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

6. मूल जॉच में उत्पाद के दायरे को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

‘सैकरीन एक गैर-पोषक स्वीटनर है और उसे केन सुगर का कम कैलोरी का प्रतिस्थापन माना जाता है। प्राथमिक रूप से सैकरीन दो प्रकार अर्थात् घुलनशील और अघुलनशील की होती है। बाजार शब्दाली में घुलनशील सैकरीन को सोडियम सैकरीन कहा जाता है जबकि अघुलनशील सैकरीन को अघुलनशील सोडियम सैकरीन कहा जाता है। सोडियम सैकरीन के अलावा, सैकरीन कैल्शियम और जिंक सैकरीन की किस्में हो सकती हैं। सैकरीन को दो भौतिक रूपों अर्थात् दानेदार और पाउडर रूप में उत्पादित किया जाता है। सोडियम सैकरीन दानेदार रूप में उस स्थिति में जब वह घुल जाता है प्रयोग किया जाता है, पाउडर रूप जो पीसा और स्प्रे ड्राइड होता है का प्रयोग ड्राइ मिश्रण और भेषजों में प्रयोग किया जाता है। यह जल में थोड़ा घुलनशील होता है। सैकरीन के अघुलनशील रूप का प्रयोग भेषजों और चिकित्सा अनुप्रयोगों में होता है। सैकरीन का प्रयोग अनेक उद्योगों जैसे खाद्य और पेय, पर्सनल केयर उत्पाद, टेबल टाप स्वीटनर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ब्राइटनेर्स, भेषज आदि में किया जाता है। सैकरीन चीनी से 500 गुना अधिक मिठास वाला होता है। वर्तमान जॉच के दायरे के भीतर सैकरीन के सभी प्रकार आते हैं। निर्णायक समीक्षा जॉच होने के कारण, पीयूसी पूर्ववर्ती जॉचों के समान रहेगा।

7. वर्तमान जॉच के लागू शुल्क की निर्णायक समीक्षा जॉच होने के कारण, विचाराधीन उत्पाद मूल जॉच में परिभाषित के समान ही रहेगा।

8. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि उनके द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देश से आयातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से समान वस्तु हैं। आयातित उत्पाद और घरेलू रूप से उत्पादित वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं।

9. इस उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अधीन उपशीर्ष सं. 29251100 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है।

घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

10. निर्णायक समीक्षा के लिए अनुरोध मै. स्वाति पेट्रो प्रोडक्ट्स प्रा. लि., मै. श्रीवरदायिनी कैमिकल इंड. प्रा. लि. और मै. ए एस कैमोप्लार्मा प्रा. लि. द्वारा दायर किया गया है। मै. ब्लू सर्कल आर्गेनिक्स प्रा. लि. द्वारा याचिका का समर्थन किया गया है। भागीदार कंपनियां और समर्थकों का संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है। अतः आवेदन को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किया गया माना जाता है और उक्त भागीदार कंपनियों को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर क्षति जॉच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग माना गया है।

इ. शामिल देश

11. शुल्क चीन जनवादी गणराज्य के विरुद्ध लागू हैं। अतः इस निर्णायक समीक्षा में उक्त देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर लागू शुल्क शामिल होगा।

च. निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

12. पाटन के जारी रहने और क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना को सही सिद्ध करते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करते हुए, प्राधिकारी एतद्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार समीक्षा की शुरुआत करते हैं ताकि इस बात की समीक्षा की जा सके कि क्या संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर 13 जनवरी, 2012 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 7/2012 द्वारा लगाये गए शुल्क के हटने से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का पाटन जारी रहेगा या उसकी पुनरावृत्ति होगी और घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहेगी या उसकी पुनरावृत्ति होगी और क्या संबद्ध वस्तु के विरुद्ध लागू निश्चयात्मक शुल्क को जारी रखने की जरूरत है।

छ. प्रक्रिया

13. इस समीक्षा में दिनांक 7 दिसंबर, 2011 की अधिसूचना सं. 15/20/2010-डीजीएडी जिसमें चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सैकरीन के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की गई थी, के सभी पहलू शामिल होंगे। संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

(i) जाँच अवधि

14. इस समीक्षा के प्रयोजनार्थ जाँच अवधि जुलाई 2015 से सितंबर 2016 (15 महीनों) की अवधि जाँच अवधि के रूप में है। तथापि क्षति जाँच के प्रयोजनार्थ 2013-14, 2014-15, 2015-16 और जाँच अवधि के आकड़ों पर विचार किया जाएगा।

(ii) सूचना प्रस्तुत करना

15. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उसके दूतावास/प्रतिनिधियों के जरिए उनकी सरकार, संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्तारों और भारत में घरेलू उद्योग को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नीचे दिए गए पते पर प्रस्तुत कर सकें:

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग
कमरा सं. 15, चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

16. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उक्त अनुरोध का अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना होगा।

17. संबद्ध देश के उत्पादक/निर्यातक को विनिर्माण, उत्पादन और घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की बिक्री और भारत और अन्य देशों को निर्यात के संबंध में बाजार दशाओं की मौजूदगी को प्रदर्शित करना होगा। इस प्रयोजनार्थ, उत्पादक/निर्यातक निम्नलिखित के संबंध में स्पष्टीकरण दे सकते हैं या पर्याप्त सूचना उपलब्ध करा सकते हैं:

- क) कीमत, लागत, कच्ची सामग्री सहित निविष्टि, प्रौद्योगिकी और श्रम की लागत, उत्पादन, बिक्री और निवेश के संबंध में निर्णय बाजार संकेतकों जो आपूर्ति और मांग को दर्शाते हैं और राज्य के किसी हस्तक्षेप के बिना लिये जाते हैं और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत बाजार मूल्य को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करती है।
- ख) उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति किसी विकृति से प्रभावित नहीं हैं।
- ग) उत्पादक/निर्यातक दिवालिया और संपत्ति कानून के अधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन के लिए विधिक निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं।
- घ) विनिमय दर में परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते हैं।

(iii) समय-सीमा

18. वर्तमान जाँच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजा जाना चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

19. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच की शुरुआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने या अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

ज. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

20. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।

21. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। समस्त हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय रूपांतरण की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय रूपांतरण की पाँच (5) प्रतियां सॉफ्ट प्रतियों के साथ, प्रस्तुत की जानी चाहिए।

22. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

23. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध / रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

24. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

25. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

झ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

26. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

ञ. असहयोग

27. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

इंद्रजीत सिंह, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th January, 2017

Case No. SSR-3/2017**(Sunset Review Investigation)****Subject: Initiation of Sunset Review of Antidumping Duty on import of Saccharin from China PR.**

F. No. 15/23/2016-DGAD.—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), vide Notification No. 14/27/2004-DGAD dated 4th July 2005, initiated an antidumping investigation into alleged dumping of Saccharin from China PR and consequent injury to the domestic industry. Preliminary findings were issued on 1st April 2006 and Final Findings were issued on 3rd January 2007. Definitive anti-dumping duties were imposed, vide Ministry of Finance Notification dated 19th March, 2007, on the imports of Saccharin (herein after referred to as the subject goods) from China PR (hereinafter referred to as the subject country).

2. Subsequently the Authority initiated a sunset review of the above antidumping duty vide notification dated 31st May, 2010 and recommended continued imposition of definitive antidumping duties on the imports of the subject goods originating in or exported from the above country, vide Final Finding Notification No. 15/20/2010-DGAD dated 7th December, 2011 and the duties were extended, vide Customs Notification No. 7/2012-Cus dated 13th January 2012, for a further period of 5 years i.e., till 12th January 2017.

A. Request for initiation of Sunset Review

3. Whereas, in terms of Section 9 A (5) the Customs Tariff Act, 1995, read with Rule 23 of the Rules, the antidumping duty imposed under the said Act shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, unless in a review, initiated before the expiry of the duty, the Designated Authority concludes that the cessation of the duties is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantial request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the date of the expiry of the measure, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

4. And Whereas, a petition has been filed by M/s Swati Petro Products Pvt. Limited, M/s Shree Vardayini Chemical Ind. Pvt. Ltd. and M/s A S Chemoplarma Pvt. Limited (hereinafter referred to as 'petitioners'), in accordance with the Act and the Rules, seeking initiation of a sunset review of the Anti-dumping duty in force on import of Saccharine for extending the duties for a further period of 5 years, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the above goods originating in or exported from the above country and consequent injury to the domestic industry.

B. Grounds for review

5. The request is for continuation of the antidumping duties in force based on the grounds that dumping of the subject goods has continued in significant volume from the subject country and the expiry of the measure would be likely to result in continuation and intensification of dumping from that country because of availability excess capacities in the subject country and significant export orientation of the producers in that country. It has been submitted that though the condition of the domestic industry has improved due to imposition of the antidumping duties, revocation of the duty would lead to intensified dumping and consequent injury to the domestic industry because of significant price undercutting and underselling effects of the dumped imports from the subject country.

C. Product under consideration and like Article

6. In the original investigation, product scope has been defined as under:

"Saccharin is a non-nutritive sweetener and considered to be low calorie substitute for cane sugar. Primarily there are two types of Saccharin i.e. soluble and insoluble. In market parlance soluble saccharin is called sodium saccharin whereas insoluble sodium saccharin is called insoluble saccharin. Apart from sodium saccharin, saccharin can have other variants such as calcium and zinc saccharin. Saccharin is produced in two physical forms, viz. granular and powder. Sodium saccharin in granular form is used in situations where saccharin will be dissolved, the powder form which has been ground and spray dried is used in dry mixes and pharmaceuticals. It is slightly soluble in water. Insoluble form of saccharin is used in many pharmaceutical and medical applications. Saccharin is used in a variety of industry such as food and

beverage, personal care products, table top sweeteners, electroplating brighteners, pharmaceuticals, etc. Saccharin is more than 500 times sweeter than sugar. All forms of Saccharin are within the scope of the present investigation. Being a sunset review; the PUC is the same as in the earlier investigations.

7. Present investigation, being a sunset review of the duty in force, the products under consideration would remain the same as has been defined in the original investigation.

8. Petitioners have submitted that the subject goods produced by them are like article to the goods imported from the subject country in terms of physical and technical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The imported products and the domestically produced goods are technically and commercially substitutable, and consumers use them interchangeably.

9. The product is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under sub-headings No. 29251100.

D. Domestic industry and Standing

10. The request for the sunset review has been filed by M/s Swati Petro Products Pvt. Limited, M/s Shree Vardayini Chemical Ind. Pvt. Ltd. and M/s A S Chemoplarma Pvt. Limited. The petition has also been supported by M/s Blue Circle Organics Pvt. Ltd. The participating companies and the supporters account for a major proportion of the domestic production of the subject goods. Therefore, the application is deemed to have been made by or on behalf of the domestic industry and the above participating companies have been treated as the domestic industry under Rule 2(b) of the Antidumping Rules for the purpose of injury investigation.

E. Country involved

11. The duties are in force against the People's Republic of China. Therefore, this sunset review will cover the duty in force on the subject goods originating in or exported from the above country.

F. Initiation of Sunset Review

12. Having satisfied itself, on the basis of the positive evidence submitted by the domestic industry, substantiating the likelihood of continuation of dumping and recurrence of injury, the Authority hereby initiates a review investigation in accordance with Section 9A (5) of the Act read with Rule 23 of Antidumping Rules, to review whether revocation of the duty on imports of the subject goods originating in or exported from the subject country, imposed vide Customs Notification No. 7/2012-Cus dated 13th January 2012, shall lead to continuation or recurrence of dumping of the subject goods from the subject country and continuation or recurrence of injury to the domestic industry, and need for continued imposition of the definitive duty in force against the subject goods originating in or exported from the subject country.

G. Procedure

13. The review will cover all aspects of Final Finding Notification No. 15/20/2010-DGAD dated 7th December 2011 recommending continuation of anti-dumping duty on import of Saccharin originating in or exported from China PR. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rule *supra* shall be *mutatis mutandis* applicable in this review.

(i) Period of Investigation

14. The period of investigation for the purpose of this review shall be from July 2015 –September, 2016 (15 months) as the period of investigation (POI). However, for the purpose of injury investigation, the data of 2013-14, 2014-15, 2015-16 and the POI shall be considered.

(ii) Submission of Information

15. The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through its embassy/representatives in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry in India are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority at the following address:

The Designated Authority

Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties

Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce

Room No. 15, 4th Floor Jeevan Tara Building, Parliament Street

New Delhi-110001

16. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

17. While submitting the questionnaire response producers/exporters in the subject country may have to demonstrate prevalence of market condition related to manufacture, production, and sales of subject good in the domestic market and in export to India and other countries. For this purpose, the producer/exporter, may clarify and provide sufficient information on the following:

- a) Decision in regard to price, cost, input including raw material, cost of technology and labour, output, sales and investment, are without significant state interference and weather cost of major inputs substantially reflect market value.
- b) Production costs and financial situation does not suffer for any distortion.
- c) The producer/exporter are subject to bankruptcy and property law which guarantees legal certainty and stability for the operation of the firms.
- d) Exchange rate conversions are carried out at the market rate.

(iii) Time Limits

18. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.

19. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need for continuation, or otherwise, of the Anti-dumping measures, within 40 days from the date of initiation of this investigation.

H. Submission of information on confidential basis

20. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

21. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

22. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

23. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential, version with the confidential information preferably indexed or blanked out / summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

24. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

25. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof, or without a good cause statement on the confidentiality claim, may not be taken on record by the Authority. The Authority, on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

I. Inspection of public file

26. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

J. Non-cooperation

27. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

INDER JIT SINGH, Addl. Secy. & Designated Authority